

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या
दिनांक दिसंबर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई

श्री गौतम सिगामणि पोन
श्री कुलदीप राय शर्मा
श्री जी सेल्वम
श्री सी एन अन्नादुरई
श्री गजानन कीर्तिकर
डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
डॉ डी एन वी सेंथिलकुमार एस
डॉ सुभाष रामराव भामरे
श्री धनुष एम कुमार

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के अंतर्गत जिन परिवारों में दिव्यांगजन हैं उन परिवारों को वरीयता प्राथमिकता प्रदान करने का कोई प्रावधान है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं
- ख क्या सरकार ने पीएमयूवाई के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए मानदंड मापदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां तो पीएमयूवाई की स्थापना के बाद से अब तक बीपीएल परिवारों को प्रदान किए गए मुक्त कनेक्शनों की संख्या का अंदाज और निकोबार राज्य गुजरात तमिलनाडू और महाराष्ट्र सहित राज्य संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है
- ग सरकार द्वारा तो एलपीजी कवरेज बढ़ाने और इसकी कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं
- घ क्या सरकार द्वारा देश में पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां समस्याओं को सरकार को सूचित किया गया है सरकार के ध्यान में लाया गया है
- ड यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सामना की जाने वाली ऐसी चुनौतियों समस्याओं की प्रकृति क्या है और इन बाधाओं को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए राज्य संघ राज्यक्षेत्र वार क्या कदम उठाए गए हैं और

च पीएमयूवाई को गरीब जनता के बीच सफल योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम क्या हैं

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रामेश्वर तेली

क गरीब परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर करोड़ निशुल्क एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से दिनांक को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई की शुरुआत की गई थी और योजना के लक्ष्य को सितम्बर हासिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के अलावा करोड़ और निशुल्क एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिनांक अगस्त को उज्ज्वला की शुरुआत की गई है।

ख सरकार ने पीएमयूवाई और उज्ज्वला के क्रियान्वयन के लिए ओएमसीज को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिनांक की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई के तहत जारी कनेक्शनों के राज्य केन्द्र शासित प्रदेश वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

ग एलपीजी कवरेज का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें पीएमयूवाई के तहत निशुल्क एलपीजी कनेक्शन बाधारहित कनेक्शन देना कि ग्रा सिलिंडर किसी एक मौजूदा एलपीजी कनेक्शन धारक के लिए दूसरा कनेक्शन पीएमयूवाई सहित नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प तथा ई सब्सक्रिप्शन वाउचरों को जारी करना एलपीजी पंचायतों का आयोजन तथा राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों आदि के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं।

उज्ज्वला के तहत लाभार्थियों को निशुल्क प्रथम रीफिल और चूल्हे के साथ मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है। संभावित पीएमयूवाई लाभार्थियों को पारिवारिक ब्यौरों के लिए स्व घोषणा तथा पता के प्रमाण के साथ ऑनलाइन तरीके से नए एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

पीएमयूवाई के क्रियान्वयन के कारण राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज जो दिनांक की स्थिति के अनुसार थी दिनांक को बढ़कर हो गई है।

घ से च पीएमयूवाई के क्रियान्वयन के संबंध में पहचान किए गए पात्र लाभार्थियों की संख्या तथा राज्यों जिलों में एलपीजी कवरेज की तुलना में जारी कनेक्शनों की वास्तविक संख्या के अनुसार कड़ी निगरानी रखी जाती है। ओएमसीज को पेश आने वाली कठिनाइयों में मुख्यत परिवारों की पहचान दुर्गम क्षेत्र एलपीजी आदि की उपयोगिता के बारे में कम जागरूकता का होना है। ओएमसीज ने एलपीजी के उपयोग के फायदों का उल्लेख करके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के संबंध में श्री गौतम सिगामनी पोन और अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या के भाग ख के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक	
राज्य संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	
आंध्र प्रदेश	
अरुणाचल प्रदेश	
असम	
बिहार	
चंडीगढ़	
छत्तीसगढ़	
दादर व नागर हवेली और दमन और दीव	
दिल्ली	
गोवा	
गुजरात	
हरियाणा	
हिमाचल प्रदेश	
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	
झारखंड	
कर्नाटक	
केरल	
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	
लक्षद्वीप	
मध्य प्रदेश	
महाराष्ट्र	
मणिपुर	
मेघालय	
मिजोरम	
नगालैंड	
उड़ीसा	
पुद्दुच्चेरी	
पंजाब	
राजस्थान	
सिक्किम	
तमिलनाडु	
तेलंगाना	
त्रिपुरा	
उत्तर प्रदेश	
उत्तराखंड	
पश्चिम बंगाल	
योग	